नाम - राहुल गोयल
प्रश्नपत्र - II (इकाई - 1, 2, 3)
दिनांक - 14-02-2022

83/150

1 A संविधान सभा की लघु समितियो में से एक प्रेस गैलरी समिति थी। जिसकी प्रमुख ऊषा नाथ सेन थी। (1/2)

1 B आनंदपुर साहिब संकल्प वर्ष 1973 में पारित हुआ था। इसके तहत पंजाब को एक स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया जाना था (2)

1 C भारत में जनहित याचिका के जनक न्यायमूर्ति श्री पी एन भगवती को कहा जाता है। (2 1/2)

1 D प्रिवी पर्स भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता पूर्व के राजपरिवारो को दी जाने वाली विशेष सुविधा थी जिसे 26 वे संविधान संशोधन से 1970 में 1971 समाप्त किया गया। (2)

1 E अनुच्छेद 43 A संविधान में 42 वे संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया जिसके तहत उद्योगो के प्रबंध में कर्मकारो का भाग लेना शामिल है। (2)

1 F NSCN का पूर्ण रूप नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड है। यह एक अलगाववादी संगठन है, जो स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे है। (2)

1 G राष्ट्रीय एकता परिषद 1961 में स्थापित सरकारी सलाहकारी निकाय है जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। (2)

1 H एनजीओ दर्पण 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को एक यूनिक आईडी प्रदान कर एक मंच पर लाने का प्रयास है। (2)

कृपया पेपर को पेपर की तरह दो।

आपके उत्तर काफी अच्छे जा रहे हैं।

1 I अटल टिंकरिंग लैब्स केन्द्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) की पहल है जिसमे हाई स्कूल के छात्रों मे एक अभिनव मानसिकता का विकास किया जायेगा।

(1½)

1 J रोज बेकर एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ व सांख्यिकीविद हैं।

1 K विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) 1973, विदेशी मुद्रा संसाधनो के संरक्षण व सदुपयोग करने के लिये लाया गया था। इसे 1999 मे फेमा से प्रतिस्थापित करदिया।

(2½)

1 L जयंती पटनायक पूर्व सांसद व राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष (1992 - 95) थी।

(3)

1 M वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मतदाता को उसके मत की पुष्टि कर मतदान प्रणाली को मजबूत बनाता है।

(2½)

1 N थुंगन समिति का ~~गठ~~ गठन 1989 मे पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने हेतु किया। इसने इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की।

(2½)

1 O जिला उपभोक्ता फोरम का गठन राज्य सरकार करती है यह एक करोड तक के मामले सुन सकता है।

1986 में

(1½)

2 A सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत है क्योंकि यहाँ-

→ सभी निर्णय व कार्यवाहीयां लिखित होते हैं और उन्हें साक्ष्य रूप में सुरक्षित रखा जाता है।

→ अधीनस्थ न्यायाल इसके निर्णयों को साक्ष्य रूप में मानती है।

→ और विधायीका व कार्यपालिका भी नियम के रूप में मानती है।

→ न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दण्ड दे सकता है

→ संविधान का अनुच्छेद 129 इसे अभिलेख न्यायालय मानता है।

2 पॉइंट पहले आना चाहिए (8)

2 B लोक अदालत को सीपीसी, 1908 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त है, जो निम्न है -

→ किसी गवाह को समन भेजना व शपथ पर उसकी समीक्षा लेना।

→ किसी दस्तावेज को प्राप्त व प्रस्तुत करने का अधिकार।

→ शपथ पत्रों पर साक्ष्यों की प्राप्ति।

→ वे समस्त शक्तियाँ जो सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं।

→ लोक अदालत में होने वाली कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत निर्धारित नियमों के मुताबिक अदालती कार्यवाही माना जाएगा।

(3½)

2 C उद्देश्य संकल्प पाकिस्तान की संविधान सभा द्वारा मार्च 1949 को पाकिस्तानी रियासत व हुकूमत के नीति निर्देशक के रूप में पारित किया गया। इसके अनुसार पाकिस्तानी संविधान का आधार इस्लामी लोकतंत्र व सिद्धान्त होंगे।

दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारतीय संविधान सभा में रखा जिसे सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसमें अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सामाजिक व अन्य वैध अधिकारों की रक्षा की बात कही गई।

(3½)

2 D (1½)

संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44 वे संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार मे परिवर्तित कर दिया गया था । 44 वे संविधान संशोधन से पहले यह अनुच्छेद -31 के अन्तर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद 300(A) के अन्तर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया । जब यह मौलिक अधिकार था तब यह देश के विकास (भूमि-अधिग्रहण) मे बाधक था ।

प्रश्न के अनुरूप उत्तर दें।

भारत सरकार द्वारा भूमि सुधार सामाजिक न्याय

2 E (3½)

देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है जिन्हे आचार संहिता कहते है । लोकसभा / विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है । यह चुनाव की तारीख घोषित होने से चुनाव परिणाम आने तक लागू रहती है । इस दौरान सरकार कोई नया निर्माण कार्य या लोकलुभावन नीति नही ला सकती । इसे और यूजर-फ्रेंडली बनाने हेतु चुनाव आयोग ने C-VIGIL एप लोंच किया ।

2 F (3½)

' स्ट्रिंग ऑफ पर्ल ' हिंद महासागर क्षेत्र में संभावित चीनी इरादों से संबंधित एक भू-राजनीतिक सिद्धान्त है जो चीनी मुख्य भूमि से सूडान पोर्ट तक फैला हुआ है । वर्ष 2017 में चीन ने जिबूती में अपनी पहली विदेशी सैन्य सुविधा शुरू की और वह अपने महत्वकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के रूप मे श्री लंका, बांग्लादेश, अफ्रीका के पूर्वी तट आदि क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा में निवेश कर रहा है । ये गतिविधियाँ चीन की भारत को घेरने से संबंधित हैं, जिसे "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल" कहा जाता है ।

2 G हाल ही मे सर्वोच्च न्यायालय मे पाँच न्यायाधीशो की पीठ ने निर्णय लिया है कि वर्ष 1992 मे नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा आरक्षण की 50% सीमा (इंद्रा साहनी निर्णय) के निर्णय को बाद में हुए संवैधानिक संशोधनो तथा सामाजिक परिवर्तनो के कारण संशोधित किया जाना चाहिए। कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र मे मराठा आरक्षण, म.प्र. मे ओबीसी आरक्षण, राजस्थान आदि राज्यों मे आरक्षण की मांग 50% की सीमा का उल्लंघन कर रही है 103 वाँ संविधान संशोधन मे (EWS) भी 50% की सीमा का उल्लंघन हुआ है।

2 H भारतीय संविधान में 73 वे संविधान संशोधन, 1992 पंचायती राज संस्थाओ को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसमें महिलाओ 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया, कई राज्यो जैसे बिहार, म.प्र. आदि मे यह सीमा 50% है। इससे महिलाओ का राजनीतिक सशक्तिकरण तो हुआ है परन्तु अपेक्षानुसार नही क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रो में महिलाएँ अशिक्षित, अधिकारो के प्रति गैर-जागरूक, बेरोजगार, आर्थिक रूप से कमजोर है अतः महिलाओं वास्तविक सशक्तिकरण शिक्षा, जागरूकता, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना कर किया जा सकता है।

2 I भारत मे निर्णय प्रक्रिया मे सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिको को जोडने या उनसे सुझाव लेने की दर बढती जा रही है जो एक अच्छा संकेत है। भारत मे लगभग 40 करोड़ सोशल मीडिया यूजर है। वर्तमान मे सरकार कई मामलों जैसे पद्म अवार्ड, बजट आदि के संबंध मे नागरिको सुझाव मांगे। भारत मे लगभग 62 करोड इंटरनेट उपयोग कर्ता है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों मे ब्रॉडबैंड पहुंचाकर इसे और बढाकर निर्णय प्रक्रिया अधिक नागरिको को शामिल कर निर्णय को और सार्थक बनाया जा सकता है

2 (J) स्वयं सहायता समूह ऐसे समूह हैं जो स्वेच्छा से किसी विशेष कार्य के लिया बनाया गया एक छोटा समूह है। इसमे 10 - 20 सदस्य हो सकते हैं। ये सदस्य बचत तरण व सशक्तिकरण के उपकरणों द्वारा आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी करते हैं। इनका उद्देश्य उद्यमों की स्थापना, लघु बचत को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन, जातिगत विषमता दूर करना, महिलासशक्तिकरण आदि होते हैं।

3 A

* बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के साथ स्वयं को समायोजित करने के लिए भारत का संविधान इसके संशोधन का प्रावधान करता है। संविधान के भाग-20 में अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जिसकी आलोचना निम्न आधारों पर कर सकते हैं -

- संविधान में संशोधन प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति संसद के पास है। राज्य विधायिका एक मामले को छोड़कर (राज्य विधानपरिषदों के निर्माण व समाप्ति का संसद से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित करना) संविधान में संशोधन के लिए कोई विधेयक या प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकती है।
- संविधान के प्रमुख भागों में अकेले संसद द्वारा चाहे विशेष बहुमत से या साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। केवल कुछ ही मामलों में राज्यों की सहमती ली जाती है तो भी आधे राज्यों की
- संविधान उस समय सीमा को निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर राज्य विधायिकाओं को उन्हें प्रस्तुत किये गये संशोधन की पुष्टि करना चाहिये या अस्वीकार।
- संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने पर गतिरोध होने की स्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- संशोधन की प्रक्रिया एक विधायी प्रक्रिया के समान है। विशेष बहुमत को छोड़कर, संविधान संशोधन विधेयकों को संसद द्वारा सामान्य ~~विधेयकों को संसद द्वारा सामान्य~~ विधेयकों की तरह ही पारित करना होता है।

8

संशोधन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान बहुत ही स्थूल हैं। इसलिये ये मामलों को न्यायपालिका तक ले जाने की व्यापक गुंजाइश प्रदान करते हैं। इन दोषों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह प्रक्रिया सरल और आसान साबित हुई है और समाज की बदलती जरूरतों व परिस्थितियों को पूरा करने में सफल रही है।

3 B

न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमनों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की न्यायपालिका की शक्ति है जो केन्द्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। परीक्षणोपरांत यदि पाया गया कि उनसे संविधान का उल्लंघन होता है तो उन्हें अवैध, असंवैधानिक तथा अमान्य घोषित किया जा सकता है और सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती।

सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मुकदमों मे न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित करना।

वर्ष २०१४ मे न्यायपालिका में न्यायाधीशों की ~~नियुक्ति~~ नियुक्ति प्रक्रिया को व्यापक तथा समग्र बनाने के लिए तथा न्याय प्रणाली की गुणवत्ता मे सुधार लाने हेतु संसद ने एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग करने के लिये 99 वे वां संविधान संशोधन अधिनियम २०१४ पारित किया।

इस आयोग का उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को बराबर का अधिकार देना है। इससे न्यायपालिका मे कार्यपालिका के हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त हो गया जिससे न्याय व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी तथा यह अनुच्छेद 50 मे वर्णित कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की भावना के अनुकूल नहीं है। इसमे न्यायपालिका कार्यपालिका के अस्तित्व में आ सकती है।

परिणाम स्वरूप 5 जनवरी 2015 को सर्वोच्च न्यायालय मे दाखिल याचिका में इस कानून को निरस्त करने की मांग की गई। "न्यायमूर्ति जगदीश केहर की अध्यक्षता मे गठित संवैधानिक पीठ ने अक्टूबर 2015 को ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 99 वे वा संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया तथा कोलेजियम व्यवस्था को पुन: बहाल कर दिया गया।

3 (c) भारतीय समाज अपनी प्रकृति और रचना में अत्यंत विविध है। इसलिए भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। जिनमें जाति व धर्म सर्वप्रमुख हैं-

जाति - जाति मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। जातियों का राजनीतिकरण तथा राजनीति में जातिवाद भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। रजनी कोठारी के अनुसार "भारतीय राजनीतिक जातिवादी है तथा जाति राजनीतिक है।" इसका उदाहरण वर्तमान में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के चुनाव में देखा जा सकता है -

यही कारण है कि यहां भाजपा और सपा दोनो ही छोटे दलों से गठबंधन पर जोर देती हैं। यहां पहले नंबर पर ओबीसी हैं जो 42 से 45 फीसदी हैं, दलित 21-22% सवर्ण 18-20% हैं। सभी पार्टियां अपना मेनीफेस्टो इन्हीं जातिगत समीकरणों के आधार पर करती हैं। यूपी में अनुसूचित जाति व जनजाति की 86 सीटें आरक्षित हैं। जिन्हें कोई पार्टी गवाना नहीं चाहेगी। इसबार बसपा दलित-ब्राह्मण को एक साथ लाने के वादे पर चुनाव लड़ रही है।

7½

धर्म → धर्म एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करता। अनेक सांप्रदायिक पार्टियों के होने से धर्म का भी राजनीतिकरण हुआ है। जैसे वर्तमान UP चुनाव में बीजेपी राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कोरिडोर के मुद्दे पर हिंदू की भावनाओं को अपने पक्ष में करना चाहती है तो वहीं बसपा ने बड़ी मात्रा में मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुस्लिम बहुल क्षेत्र है यहाँ 9 जिलों में तो मुस्लिम 55 फीसदी के आसपास हैं। यहाँ AIMIM का प्रभाव अधिक है। प्र. में 20% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं।